Statement

Individual number of coaches running on 907/908 Himsagar Exp. as on 25-7-1987 along with their years of manufacture

S. No.	Coach No.	Railway	Class	Type	Built date
1	4863	SR	SLR	ICF all coiled	1971
2	10486	NR	WGSCZ	,,	1981
3	14009	,,	WGACCW	,,	1986
4	1183	,,	WFC	,,	1986
5	10637	,,	WGSCNY	,,	1983
6	10196	,,	,,	,,	1979
7	8075	,,	,,	,,	1979
8	1194	,,	WCB	,,	1986
9	12091	,,	WGSCNY		1983
10	12061	,,	,,	,,	1983
11	12127	,,	,,	,,	1986
12	10635	,,	,,	,,	1983
13	12119	,,	,,	,,	1986
14	11215	,,	WGS	,,	1984
15	4680	SR	SLR	,,	1963

Privatisation of Road Transport

2911. SHRI SURAJ PRASAD:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to privatise road transport; and

(b) if so, what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The movement of goods by road transport is mainly in the private hands. As for passenger transportation, the State run transport undertakings taken together has the share of only 40 per cent of the traffic on the basis of fleet strength. The balance is by private operators. There is no proposal to privatise state run transport undertakings.

"हिस्टोरियन वांट्स डिस्टोरेशन रिमूव्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

2912. श्री रशीद मसूद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च 1987 के "द ट्रिब्यून" में "हिस्टोरियन वांट्स डिस्टारेशन रिमूव्ड" शीर्षक के अन्त-

र्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई रचनात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकार ने उस समाचार का देखा है जिसमें डा० वी० एस० वाकनकर द्वारा व्यक्त वह वक्तव्य था कि विदेशी शासकों द्वारा उत्पन्न की गई राजनीति प्रेरित विसंगतियों का दूर करने के लिए भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए । भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय सामाजिक ज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक और अनसंधान निकायों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार पहले ही इतिहास के वस्तुपरक और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित कर रही है ।

"बेटर बुक्स फार स्कूल्स सजेस्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2913. **श्री रशीद मसूद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "बेटर बुक्स फार स्कूल्स सजेस्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) जी, हां ।

(ख) ये समाचार निजी प्रकाशकों और भारत के प्रकाशन तथा पुस्तक विक्रेता के महासंघ द्वारा आयोजित पुस्तक प्रकाशन संबंधी सेमिनार में पुस्तक विक्रेताओं द्वारा व्यक्त विचारों पर स्पष्टतः आधारित है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने कोटि तथा प्रमाणिक पुस्तकों को तैयार करने का निरंतर प्रयास किया है और उन्हें समय पर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद पुस्तकों के उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए लगातार पुरस्कार जीतता रहा है और अकेले इस वर्ष के दौरान ही इसने पुस्तकों के उत्कृष्ट मुद्रण और डिजाइन तैयार करने में 7 (सात) पुरस्कार जीते हैं ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के देश के विभिन्न भागों में स्थित बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने पुस्तकों के संवितरण को और सरल बनाने के प्रयास में संघ शासित प्रदेश दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर 14 थोक बिक्री एजेंसियां नियुक्त की हैं ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास "नेहरू बाल पुस्तकालय" नामक योजना के अन्तर्गत 5—15 आयु वर्ग के लिए बाल पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत उत्पन्न की जा सके ।